

The advertisement features a bright yellow background with a sunburst pattern. At the top left, a speech bubble contains the text 'BOOK! NOW!'. At the top right, the 'Harsh Media' logo is displayed. In the center, a white rectangular box contains a cartoon illustration of a face with large, expressive eyes. Below the eyes, the text 'अब हर नज़र आपके Brand पर !' is written in Hindi. Underneath this box, a list of services is provided in two columns. At the bottom, a large black banner displays the phone number '8253029444 | 8435918888'. The footer contains contact information including a website, email, and Instagram handle.

संपादकीय

सुखना अब ‘रामसर’

झील के संरक्षण की प्रतिबद्धता दिखाने का वक्त

यह सुखद ही है कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चंडीगढ़ की सुखना झील के महत्व को स्वीकारा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सुखना वेटलैंड को ‘रामसर साइट’ का दर्जा मिलना चंडीगढ़ के लिये गर्व की बात है। लेकिन यह सम्मान मिलना हमारी जवाबदेही को भी बढ़ाना वाला भी है। साथ ही मानकीकरण, एक ऐसे पारिस्थितिकीय तंत्र को संरक्षित करने की तत्काल आवश्यकता पर बल देता है- जो इसके तल पर गाद जमा होने,जल भंडारण क्षमता घटने तथा बढ़ते पर्यावरणीय दबावों के कारण हमारे सामने चुनौती पैदा कर रहा है। वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय पहचान पाने वाला शहर का यह पहला वेटलैंड यानी आर्द्रभूमि, केवल सरकारी उपलब्धि का

“

ध्यान रहे कि सुखना झील का जलग्रहण क्षेत्र चंडीगढ़ के बाहरी इलाके तक फैला हुआ है। इसलिए पंजाब और हरियाणा के साथ समन्वय भी उतना ही जरूरी है। इसमें दो राय नहीं कि कोई भी आर्द्रभूमि, पारिस्थितिकीय तंत्र के लिये हमारी अत्यंत महत्वपूर्ण धरोहर होती है।

लेते शहरीकरण की समस्या का सामना कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कश्मीर की तुलर झील का जल क्षेत्र सिमट रहा है। उसकी स्थिति समय के साथ खराब हुई है। कमोबेश ऐसी ही समस्या ओडिशा की चिल्का झील की भी है, जो गाद जमा होने की चुनौती से जूझ रही है। ऐसे में चंडीगढ़ प्रशासन को आने वाले समय में सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिये दूरगामी नीतियों का अनुपालन करना होगा।

अब शासन-प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि सुखना झील की जल भंडारण क्षमता, इसके तल में गाद जमने से लगातार कम हो रही है। वहीं दूसरी ओर जल स्तर में उतार-चढ़ाव और प्रदूषण का बढ़ना बताता है कि यहां निरंतर उपचारात्मक प्रयासों की जरूरत है। हम कभी-कभार गाद निकालने की कवायद करके समस्या का समाधान नहीं कर सकते। वास्तव में मिट्टी का संरक्षण, जल निकासी, चैनलों की सुरक्षा, वैज्ञानिक जल प्रबंधन और प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिये एकीकृत रणनीति बनाने की जरूरत होगी। वहीं रामसर का दर्जा मिलने का यह मतलब कदापि नहीं है कि यहां निर्माण कार्य नहीं हो सकते, या इससे फैंडिंग की गारंटी मिलती है। हमें यह भी नहीं मान लेना चाहिए कि यह दर्जा मिलने से पारिस्थितिक नुकसान को रोका जा सकता है। निस्संदेह, प्रशासन को सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिये गंभीर प्रयास करने होंगे। इसके साथ ही जैव विविधता और पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिये पलल करनी चाहिए। इसके अलावा संरक्षण योजनाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू करना चाहिए। ध्यान रहे कि सुखना झील का जलग्रहण क्षेत्र चंडीगढ़ के बाहरी इलाके तक फैला हुआ है। इसलिए पंजाब और हरियाणा के साथ समन्वय भी उतना ही जरूरी है। इसमें दो राय नहीं कि कोई भी आर्द्रभूमि, पारिस्थितिकीय तंत्र के लिये हमारी अत्यंत महत्वपूर्ण धरोहर होती है। इसके संरक्षण का असली मानक यह होगा कि झील का परिदृश्य अधिक स्वस्थ हो, उसकी जल भंडारण क्षमता बहाल की जाए और साथ ही वन्यजीवों के फलने-पूलने के लिये अनुकूल वातावरण बन सके। विश्वास किया जाना चाहिए कि सुखना के संरक्षण से अब हर साल आने वाले प्रवासी पक्षियों की संख्या में वृद्धि होगी। साथ ही ईको टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल सकेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि सुखना झील के अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में उभरने से दुनियाभर के पर्यावरण और पक्षियों के प्रेमियों की आवक बढ़ सकती है। निस्संदेह, इससे चंडीगढ़ शहर की पहचान बढ़ेगी और ईको-टूरिज्म बढ़ने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

विश्वनाथ सचदेव

हमें इस बात पर गर्व करना चाहिए कि हमारा

भारत बहुधर्मी है। और गर्व इस बात पर भी करना

चाहिए कि अलीमुद्दीन स्ट्रीट पर बसने वाले स्वयं

को हिंदू-मुसलमान से पहले इंसान समझना

चाहते हैं। यही बात हर भारतीय को समझनी

होगी। सारे मोहल्ले में त्योहार का माहौल है।

दुर्गापूजा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यहां के

युवा पूरे जोर-शोर से लगे हुए हैं-इस संकल्प के

साथ कि कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पश्चिम

बंगाल की राजधानी कोलकाता के इस मोहल्ले का

नाम है अलीमुद्दीन स्ट्रीट। मुस्लिम-बहुल इलाके

में सालों से दुर्गापूजा की तैयारियां इसी जोश-

खरोश के साथ होती थीं। फिर मनमुटाव की कुछ

घटनाएं हुईं और पूजा का यह क्रम टूट गया था।

पांच साल पहले फिर शुरू हो गया और अब यह

जोश साल-दर-साल बढ़ता ही दिख रहा है।

विशेषता यह भी है कि तैयारियों में आगे बढ़कर

हाथ बंटाने वालों में ज्यादातर युवा मुसलमान हैं।

यहां पूजा पूरे विधि-विधान से होती है-और हिंदू-

मुसलमान मिलकर करते हैं!

जनकल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीण विकास को गति

आजीविका के नए अवसरों से मजबूत हो रहा सरगुजा

विशाल कुमार जायसवाल
सहायक सूचना अधिकारी अम्बिकापुर

नोनी सुरक्षा योजना, राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना, ग्रामीण रोजगार के अंतर्गत आजीविका डबरी तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी पहले परिवारों को आर्थिक सुरक्षा, रोजगार और बेहतर आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने में सहायक हो सकती हैं। इन योजनाओं का महत्व इस बात में है कि वे स्थानीय जरूरतों और संसाधनों को विकास के अवसरों से जोड़ती हैं।

बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और उच्चल भविष्य के लिए समय रहते आर्थिक प्रावधान करना परिवारों को भरोसा प्रदान करता है। छत्तीसगढ़ शासन की नोनी सुरक्षा योजना के अंतर्गत अम्बिकापुर विकासखंड की ग्राम पंचायत कृष्णापुर निवासी श्रीमती मानती राजवाड़े की बेटी आंचल राजवाड़े को एक लाख रुपये का बॉन्ड प्राप्त हुआ है। यह बॉन्ड भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है।

मानती राजवाड़े के लिए बेटी की शिक्षा और भविष्य की जरूरतों की व्यवस्था करना महत्वपूर्ण है। योजना के अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अनुसार बेटी के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर मिलने वाली राशि का उपयोग आगे की पढ़ाई और अन्य आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता। इससे भविष्य में उच्च शिक्षा से जुड़े खर्चों की व्यवस्था करने में परिवार को सहायता मिलने की उम्मीद है। यह पहल बेटियों के भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण है।

सरगुजा जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि के साथ पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। डेयरी व्यवसाय किसानों और ग्रामीण परिवारों को नियमित आय का साधन उपलब्ध करा सकता है। राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर लगमांग निवासी मनोज कुमार पटेल ने अपने डेयरी व्यवसाय को



आगे बढ़ाया है।

मनोज कुमार पटेल प्रतिदिन लगभग 30 लीटर दूध का विक्रय कर करीब 1,200 रुपये की दैनिक आय अर्जित कर रहे हैं। उनके अनुसार, दूध की बिक्री से होने वाली मासिक आय में से खर्च निकालने के बाद लगभग 15 हजार रुपये की बचत हो रही है। पशुपालन के माध्यम से उन्हें नियमित आय का अवसर मिला है, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिल रही है।

डेयरी व्यवसाय की उपयोगिता इस बात में भी है कि इससे ग्रामीण परिवारों को केवल मौसमी कृषि आय पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। दूध उत्पादन और उसकी बिक्री से नियमित आर्थिक गतिविधि बनी रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल संसाधनों का संरक्षण आजीविका और कृषि विकास से सीधे जुड़ा हुआ है। वर्षा जल का संग्रहण सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के साथ मछली पालन जैसी गतिविधियों के लिए भी उपयोगी हो सकता है। ग्राम निवासी फूला राम पहाड़ी कोरवा की कहानी इसी दिशा में एक उदाहरण प्रस्तुत करती है।

खाली पड़ी जमीन पर आजीविका डबरी का निर्माण किया गया, जिसमें वर्षा जल का संचय कर मछली पालन शुरू करने का अवसर मिला। इससे परिवार के लिए अतिरिक्त आय का साधन विकसित होने की संभावना बनी है। ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत निर्मित ऐसी परिसंपत्तियां स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर आजीविका के अवसर तैयार करने में सहायक हो सकती हैं।

इसी तरह ग्राम के बाबूनाथ के खेत में डबरी के गहरीकरण से जल संग्रहण और सिंचाई की सुविधा बेहतर हुई। पानी उपलब्ध होने से उन्हें सब्जी उत्पादन में मदद मिली और मछली पालन की संभावनाएं भी विकसित हुईं। खेती और मछली पालन को एक साथ अपनाने से ग्रामीण परिवारों को आय के एक से अधिक स्रोत विकसित करने का अवसर मिल सकता है।

जल संरक्षण के कार्यों को आजीविका से जोड़ने पर उनका महत्व और बढ़ जाता है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार डबरी का उपयोग सिंचाई, सब्जी उत्पादन और मछली पालन के लिए किया जा

सकता है। इससे ग्रामीण रोजगार, कृषि उत्पादन और प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग को प्रोत्साहन मिलता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति बढ़ाने के लिए सड़क संपर्क का बेहतर होना आवश्यक है। सड़कें गांवों की शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार और रोजगार के अवसरों से जोड़ती हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अम्बिकापुर-दरिमा- 3.85 किलोमीटर लंबी सड़क का नवीनीकरण 57.83 लाख रुपये की लागत से पूरा किया गया। सड़क का नवीनीकरण होने से क्षेत्र में आवागमन की सुविधा बेहतर हुई है। ग्रामीणों, विद्यार्थियों, किसानों और अन्य राहगीरों को दैनिक जरूरतों के लिए आने-जाने में सुविधा मिलने के साथ आसपास के बाजारों और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच बेहतर बनाने में सहायता मिलती है।

अच्छी सड़कें कृषि उपज के परिवहन, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और विद्यार्थियों के नियमित आवागमन के लिए भी उपयोगी हैं। इस प्रकार ग्रामीण अथोरसंरचना में सुधार का लाभ अनेक

क्षेत्रों में मिलता है। सड़क संपर्क मजबूत होने से ग्रामीणों के लिए उपलब्ध अवसरों तक पहुंच आसान होती है और क्षेत्र के समग्र विकास को आधार मिलता है।

सरगुजा जिले में सामने आए ये उदाहरण ग्रामीण विकास के अलग-अलग पहलुओं को उजागर करते हैं। नोनी सुरक्षा योजना बेटियों के भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा का अवसर देती है, डेयरी व्यवसाय परिवारों को नियमित आय उपलब्ध कराने में मदद करता है और आजीविका डबरी जल संरक्षण के साथ खेती तथा मछली पालन को बढ़ावा देने की संभावनाएं पैदा करती है। वहीं, बेहतर सड़क संपर्क ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार और अन्य जरूरी सेवाओं तक पहुंचने में सहायक होता है।

सरगुजा की विकास यात्रा यह दर्शाती है कि आर्थिक सुरक्षा, आजीविका के साधन और आधारभूत सुविधाएं मिलकर ग्रामीण परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखती हैं। योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और हितग्राहियों की सक्रिय भागीदारी इन अवसरों को स्थायी उपलब्धियों में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

महिला खिलाड़ियों के लिए बने मजबूत खेल नीति

डॉ. जगमती संगवान

हालिया एशियाई खेलों में हरियाणा की महिला खिलाड़ियों का प्रदर्शन दमदार रहा जो उनके मजबूत इरादों और सामाजिक समर्थन का सबूत कहा जाएगा। इस दिशा में परिणाम और बेहतर हों इसके लिए महिला-केंद्रित खेल नीति चाहिए। वहीं देहात में खेल सुविधाएं बढ़ाने और लोकप्रिय खेल-संस्कृति के विकास की जरूरत है।

जापान के आयाची नागोया में हाल ही में संपन्न हुए बीसवें एशियाई खेलों में हरियाणा की महिला खिलाड़ियों द्वारा जीते गए ढेर सारे मेडल प्रमाण हैं कि पिछले दिनों खेल जगत में सामने आई संस्थागत यौन शोषण की घटनाओं के बावजूद उनके हौसले बुलंद हैं। यह इस्तीफा संभव हो पाया कि प्रदेश की सिविल सोसायटी अपनी बेटियों के न्याय के संघर्ष में साथ खड़ी रही। चाहे वह कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण का मामला हो या प्रदेश के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह का, या फिर

सिस्टम का रवैया।

गर्व व खुशी का विषय है कि हमने बेटियों के खेल कैरियर को प्रतिक्रियावादी ताकतों की बलि नहीं चढ़ने दिया। उल्लेखनीय है कि 2026 एशियाई खेलों में हरियाणा ने कुल 32 पदकों का योगदान किया, जिनमें 14 स्वर्ण, 9 रजत तथा 9 कांस्य पदक शामिल हैं। इन 14 स्वर्ण में से 8 सिर्फ महिलाओं ने जीते, जिनमें दो व्यक्तिगत तथा 6 टीम गेम में जीते गए। यह सराहनीय उपलब्धि है। गौर करने लायक है कि हरियाणा की बेटियों की प्रतिभा-प्रदर्शन का दायरा भी निरंतर बढ़ रहा है। अब वे केवल कुश्ती, बॉक्सिंग या कबड्डी आदि ताकत-आधारित खेलों में ही जीत हासिल नहीं कर रही हैं, बल्कि मानसिक स्थिरता, एकाग्रता, प्रतिक्रिया नियंत्रण, स्टीकाता आदि की जरूरत वाले खेलों, जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, स्केट्स, एमएमए, गोल्फ और क्रिकेट में भी धाक जमा रही हैं। इसका अर्थ है कि अब ‘बेटियों को मजबूत बनाओ, खेल-कूद में आगे लाओ’ आदि महिला आंदोलन द्वारा



गढ़े गए नारों का महत्व अभिभावक समझ रहे हैं। वहीं अब केंद्र सरकार के नारे ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ’ को चरितार्थ करने की जरूरत है।

इन नारों को चरितार्थ करने का मतलब है कि एक महिला खेल नीति बनाई जाए, जिसका सरोकार महिला खिलाड़ियों के आसपास विभिन्न स्तरीय खेल सुविधाओं

का निर्माण करना हो। क्योंकि खेल लड़कियों के जीवन में मनोरंजनकारी व स्वास्थ्यवर्धन की गतिविधि ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास-वर्धन की गतिविधि भी हैं। आजकल मेडल विजेता युवतियों को जो सम्मान दिया जाता है, उससे राज्य के गिरते लिंगानुपात पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। महिला खेल गतिविधियों पर ज्यादा से ज्यादा बजट लगाने की जरूरत है। खेल के मैदान, कोचिंग सुविधा और खेल का सामान पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराया जाए। हालाँकि जिस क्षेत्र में जिस खेल की ज्यादा प्रतिभा नजर आए, उस पर अग्रस्थ ध्यान दिया जाए। अच्छी खेल सुविधाएं शहरों तक सीमित हैं परंतु खेलों में तुलनात्मक रूप से ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी ज्यादा है। अतः खेल सुविधाओं का ढांचा उनके आसपास उपलब्ध करवाना महिला खेल नीति का सरोकार हो। कुछ गांवों में खेल स्टेडियम हैं, मगर कोच, ग्राउंडमैन आदि नियुक्त नहीं। दूसरी तरफ अगर हम पिछले यानी 2023 के एशियाई खेलों में जीते गए मेडल

और अभी 2026 में हमारे देश द्वारा जीते गए मेडल (107: 85) की तुलना करें, तो हमारी जीत में भारी गिरावट दर्ज होती है। इससे हमें कुछ सबक सीखने की जरूरत है। हमें अपने खेल के नजरिए में आमूल-चूल परिवर्तन की जरूरत है।

अभी हमारा पूरा जोर कुछ प्रतिभावान खिलाड़ियों को छोटकर खेल आयोजनों से ठीक पहले उन्हें प्रशिक्षित करने पर है। जबकि दुनिया में खेल शक्ति के रूप में उभर रहे देशों का अनुभव लोकप्रिय खेल-संस्कृति निर्मित करने पर है, जहां खेलों के केंद्र में स्वस्थ नागरिक समाज का निर्माण है, न कि मेडल जीतना। वे हर आयुवर्ग के अनुसार खेल का मूलभूत ढांचा खड़ा करना, जिसमें खेल मैदान, कोचिंग, खेल-सामान आदि का प्रबंधन शामिल है। बड़ी आबादी को खेल के दायरे में लाकर उनमें से प्रतिस्पर्धा के लिए खिलाड़ियों का चुनाव करते हैं। हमारे देश में आबादी का 3 प्रतिशत भी खेलों में भागीदार नहीं क्योंकि यहां खेलों के सामाजिक-आर्थिक पहलुओं की उपेक्षा हुई है।

बहुधर्मी भारत में महकती रहे साझा संस्कृति



मैंने गरबा के एक शानदार कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। आयोजन देखने वालों में मैंने मुसलमानों को भी देखा था। किसी के आने-जाने पर प्रतिबंध नहीं था। पर पिछले एक अर्से में इस परंपरा में भी बदलाव आया है। खुलेआम कहा जा रहा है कि गैर-हिंदुओं को इसमें भाग नहीं लेना चाहिए। देश के एक वरिष्ठ राजनेता ने तो स्पष्ट घोषणा कर दी है कि यदि संप्रदाय विशेष के लोगों को गरबा में भाग लेना है, तो उन्हें ‘घर-वापसी’ करनी होगी। ऐसे सामाजिक-धार्मिक कार्यक्रम में असामाजिक तत्वों की घुसपैठ को रोकने की बात तो समझ आती है, पर यह कहना कहाँ तक उचित है कि गैर-हिंदू ही असामाजिक तत्व हैं? और फिर इस बात का क्या तुक है कि ‘घर-वापसी’ करने वाला असामाजिक तत्व नहीं रहेगा? आवश्यकता इस बीमार सोच को बदलने की है कि धर्म के आधार पर व्यक्ति की नीयत को समझा जा सकता है। घर-वापसी वाली यह बात अब अक्सर होने लगी है।

औलाद है, इंसान बनेगा।’

यह इंसान होना ही व्यक्ति की सच्ची और पहली पहचान है। कोई भी व्यक्ति हिंदू या मुसलमान होने से पहले ‘कुछ’ तो था। इस ‘कुछ’ को समझने की आवश्यकता है। यही ‘कुछ’ व्यक्ति के इंसान होने की पहचान है। आज आवश्यकता इस पहचान को बनाए रखने की है—‘मंदिर-मस्जिद तो बाद के हैं,हम उससे पहले भी तो थे/हम उससे पहले जो भी थे/उस सच को जिंदा रखना है।’ आज इस ‘सच’ को समझने की आवश्यकता है—यह सच हमें बताता है कि हमारा हिंदू या मुसलमान होना, अथवा सिख या ईसाई होना, एक संयोग मात्र है। मेरा जन्म जिस परिवार में हुआ, वह मेरे धर्म का आधार बन जाता है, पर व्यक्ति के इंसान होने और इंसान बने रहने की कोशिश करनी पड़ती है। जब कोई मुसलमान पूरी निष्ठा और आस्था के साथ मां दुर्गा की मूर्ति बनाता है, तो वह अपने इंसान होने का प्रमाण दे

रहा होता है और यही बात उस हिंदू मां पर भी लागू होती है, जो अपने बेटे को ताजिए के जुलूस में ले जाकर उसकी बेहतरी की दुआ करती है।

बहरहाल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कुछ अर्सा पहले न्यूयॉर्क के एक सम्मेलन में कहा था कि ‘जो हिंदू यह मानता है कि मुसलमानों को भारत से बाहर निकाल देना चाहिए, वह हिंदू नहीं रह सकता।’ उन्होंने यह भी कहा था कि हिंदू शब्द को एक विशेष भाषा, पूजा-पद्धति या जीवन-शैली तक सीमित नहीं किया जा सकता। इसमें इंसानों की तमाम विविधताएं शामिल हैं। इस विविधता का सम्मान होना चाहिए। यह विविधता इंसान की ताकत है। मोहन भागवत की किसी बात से आप असहमत हो सकते हैं, पर उनकी यह बात सोचने के लिए बाध्य करने वाली है कि भारत में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। इस हिंदू को भारतीय कहकर हम अनावश्यक विवादों से बच सकते हैं। हमें इस बात पर गर्व करना चाहिए कि हमारा भारत बहुधर्मी है। और गर्व इस बात पर भी करना चाहिए कि अलीमुद्दीन स्ट्रीट पर बसने वाले स्वयं के हिंदू-मुसलमान से पहले इंसान समझना चाहते हैं। यही बात हर भारतीय को समझनी होगी।

‘ईश्वर-अल्लाह तेरा नाम’ कहने वाले गांधी ने हमें एक इंसान की तरह जीने का रास्ता दिखाया था। आज उस राह पर चलने की आवश्यकता है। यह देश का दुर्भाग्य ही होगा यदि ईश्वर के साथ अल्लाह को जोड़ने वाले गांधी को समझने के बजाय हम इस बात की शिकायत करें कि नरसी के भजन में गांधी ने यह पंक्ति क्यों जोड़ दी? हमारा भारत तो ‘ईश्वर एक है’ का संदेश देता है, तो फिर धर्म के नाम पर बांटने की कोशिशों को साजिश क्यों न माना जाए? यह सवाल हर सच्चे भारतीय को अपने आप से पूछना होगा।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

Since 1972



CROWN[®]-TV

Choice Of Millions

**LED / Washing Machine
Cooler / Fridge
Available All Size**






CONTACT :

Atlas Radio Traders (Crown)
Sect.-3, D-48, Ward No. 13
Devendra Nagar, Raipur (C.G.) 492009
Near Akash Gas Agency Line
Mob.: 98262 52372

खास खबर



बिहान गढ़ कलेवा से बदली 12 महिलाओं की जिंदगी

एमएमए। मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के मोहला विकासखंड में बिहान योजना से जुड़ी ज्योति महिला स्व-सहायता समूह की 12 महिलाएं बिहान गढ़ कलेवा का संचालन कर स्वरोजगार की नई मिसाल पेश कर रही हैं। मोहला बिहान गढ़ कलेवा में समूह की महिलाएं पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजन तैयार कर लोगों को परोस रही हैं।

इससे एक ओर लोगों को छत्तीसगढ़ की समृद्ध खानपान संस्कृति और पारंपरिक स्वाद से जुड़ने का अवसर मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को नियमित आजीविका अर्जित करने का माध्यम मिला है। समूह की सभी 12 महिलाएं आपसी सहयोग से गढ़ कलेवा का संचालन कर रही हैं और अपनी मेहनत से परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने में योगदान दे रही हैं।

ज्योति महिला स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने इस अवसर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु भैया के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को स्व-सहायता समूहों से जोड़कर आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ज्योति महिला स्व-सहायता समूह की यह पहल दर्शाती है कि स्थानीय संसाधनों, पारंपरिक हुनर और सामूहिक प्रयासों से महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बन सकती हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को भी नई पहचान दे सकती हैं।

मुख्यमंत्री निवास में गरबा महोत्सव की धूम

नवरात्रि शक्ति की आराधना और नारी सम्मान का महापर्व : साय



श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री निवास नवरात्रि की भक्ति, गरबा की लय और उत्साह के रंगों से सराबोर नजर आया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में आयोजित गरबा महोत्सव में बड़ी संख्या में माताओं-बहनों, बेटियों और गुजराती समाज के लोगों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। पारंपरिक परिधानों में सजे प्रतिभागियों ने मां दुर्गा की आराधना के साथ गरबा की मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। भक्ति संगीत और गरबा की ताल के बीच पूरा परिसर उत्सव के रंग में रंग गया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मां दुर्गा की आराधना कर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की। उन्होंने उपस्थित माताओं-बहनों, बेटियों एवं सभी श्रद्धालुओं को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नवरात्रि शक्ति की आराधना, श्रद्धा और भक्ति के साथ नारी सम्मान का महापर्व है। हमारी सनातन संस्कृति में नारी को शक्ति का स्वरूप माना गया है। यह पर्व हमें मातृशक्ति के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तीकरण के प्रति अपने दायित्वों का स्मरण कराता है।

उन्होंने कहा कि गरबा मां दुर्गा के प्रति श्रद्धा

और भक्ति को सुंदर अभिव्यक्ति होने के साथ हमारी जीवंत सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। गुजरात की धरती से निकली गरबा की परंपरा आज पूरे देश में उत्साह के साथ मनाई जाती है। ऐसे आयोजन देश की सांस्कृतिक विविधता में एकता के भाव को और मजबूत करते हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भारत के पर्व और त्योहार केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं हैं। ये परिवार और समाज को जोड़ने, आपसी प्रेम, सद्भाव और भाईचारे को मजबूत करने तथा नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और परंपराओं से परिचित कराने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं।

उन्होंने कहा कि आज गरबा देश-दुनिया में

भारतीय संस्कृति की विशिष्ट पहचान बन चुका है। छत्तीसगढ़ में भी गरबा के प्रति उत्साह लगातार बढ़ा है। बड़ी संख्या में माताओं-बहनों और बेटियों की सहभागिता इस उत्सव को और विशेष बनाती है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने गुजराती समाज के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि गुजराती समाज ने अपनी उद्यमशीलता, परिश्रम, सेवा भावना और सामाजिक एकता से देश के विकास में विशिष्ट पहचान बनाई है। छत्तीसगढ़ में भी गुजराती समाज व्यापार, उद्योग, शिक्षा, सेवा और सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से प्रदेश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

महिला सशक्तीकरण हमारी पहली प्राथमिकता

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नारी शक्ति का सम्मान हमारी संस्कृति का मूल भाव है और महिलाओं को आत्मनिर्भर तथा शक्ति बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ते हुए उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए अपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के माध्यम से लगभग 68 लाख माताओं-बहनों को प्रतिमाह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंच रही है। इससे महिलाओं को अपनी आवश्यकताओं, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार की जरूरतों को पूरा करने में आर्थिक संबल मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की 14 लाख बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। यह हमारी मातृशक्ति के परिश्रम, सामर्थ्य और आत्मविश्वास का प्रमाण है। हमारा संकल्प है कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं केवल योजनाओं की लाभार्थी ही नहीं, बल्कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में नेतृत्वकारी भूमिका निभाएं।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान सदैव सभी समाजों और संस्कृतियों की आत्मीयता से अपनाने की रही है। गुजराती समाज ने भी छत्तीसगढ़ को अपनी कर्मभूमि बनाकर यहां की सामाजिक-सांस्कृतिक यात्रा में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई है। विकसित भारत के निर्माण के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने में समाज की यह सहभागिता महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नवरात्रि हमें शक्ति, सकारात्मकता और सामूहिकता का संदेश देती है। माता रानी के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़े और प्रत्येक परिवार के जीवन में सुख, शांति

और समृद्धि आए, यही कामना है।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, विभिन्न आयोग-मंडलों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, सर्व गुजराती समाज छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष प्रोतेश गांधी, पूर्व विधायक एवं एनआर गुजराती एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष देवजी पटेल, गुजराती स्कूल के अध्यक्ष जयंती पटेल, पितुल कोठारी, नितिन डोलकिया, महेंद्र कोडियार, बाबू भाई पटेल, अशोक पटेल, मुकेश शाह, गौरंग काचा, कीर्ति व्यास, राजेंद्र फौजदार आदि उपस्थित थे।

कौशल्य से दंतेश्वरी तक यह शक्ति आराधना की भूमि

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ माता कौशल्य की पावन धरती है और यहां आदिशक्ति की आराधना की समृद्ध परंपरा सदियों से चली आ रही है। बस्तर की आराध्य मां दंतेश्वरी, डोंगरगढ़ की मां बम्लेश्वरी, रतनपुर की मां महामाया और चंद्रपुर की मां चंद्रहासिनी सहित अनेक देवी धाम प्रदेश की आस्था और सांस्कृतिक पहचान के प्रमुख केंद्र हैं। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के अवसर पर दंतेवाड़ा से डोंगरगढ़ और रतनपुर से चंद्रपुर तक माता के दरबार में श्रद्धालुओं का सेलाब उमड़ता है। पूरा छत्तीसगढ़ शक्ति की आराधना में लीन दिखाई देता है। ये शक्तिपीठ केवल हमारी आस्था के केंद्र नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और पहचान के भी महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास भी, विरासत भी की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। अपनी संस्कृति और गौरवशाली परंपराओं पर गर्व करते हुए आधुनिक भारत का निर्माण हो रहा है। इसी भावना के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार भी प्रदेश की धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है।

छत्तीसगढ़ में श्रम आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगार सृजित कर रही सरकार : मुख्यमंत्री

- निवेश के साथ बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन नई औद्योगिक नीति का प्रमुख लक्ष्य : वित्त मंत्री
- तीन हजार से अधिक उद्योगों में 50 हजार लोगों को मिला रोजगार : उद्योग मंत्री

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। नई औद्योगिक विकास नीति में ऐसे श्रम आधारित उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिनमें अपेक्षाकृत कम पूंजी निवेश के साथ बड़ी संख्या में रोजगार सृजित करने की क्षमता है। राज्य सरकार का लक्ष्य केवल निवेश आकर्षित करना नहीं, बल्कि निवेश को रोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और प्रदेश की समृद्धि का माध्यम बनाना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में यश फैन्स एंड एप्लायंसेस लिमिटेड की प्रस्तावित नई औद्योगिक इकाई के भूमिपूजन समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यश फैन्स एंड एप्लायंसेस लिमिटेड की नई इकाई छत्तीसगढ़ की औद्योगिक विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसमें 150 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश प्रस्तावित है और इससे साढ़े तीन हजार से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि छत्तीसगढ़ में ऐसे उद्योग अधिक से अधिक स्थापित हों, जो युवाओं और महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराएं। जब युवाओं को अपने ही प्रदेश में कौशल और क्षमता के अनुरूप रोजगार मिलेगा तो उनके परिवार आर्थिक रूप से सशक्त होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम के दौरान नवचयनित युवाओं को निवेश पत्र प्रदान किए और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि युवाओं के हाथ में नियुक्ति पत्र देना किसी भी औद्योगिक निवेश की सबसे सार्थक उपलब्धि है। एक रोजगार केवल एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर नहीं बनाता, बल्कि पूरे परिवार के जीवन में आर्थिक सुरक्षा और नई उम्मीद लेकर आता है। मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर तैयार करने को पहल के लिए यश ग्रुप की सराहना की।



उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नई औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 में रोजगार सृजन करने वाले उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन का प्रावधान किया है। नीति तैयार करते समय इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया है कि प्रदेश में आने वाला निवेश स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा करे। टेक्स्टाइल, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और अन्य श्रम आधारित क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के साथ ही उद्योग लगाने और संचालित करने की प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा रहा है। उद्यमियों को अनावश्यक प्रक्रियाओं और जटिलताओं से मुक्ति दिलाने के लिए लगातार सुधार किए गए हैं। जन विश्वास से जुड़े सुधारों के अंतर्गत 279 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने को विशेष पहल की गई है। विभिन्न अनुमतियों और स्वीकृतियों की प्रक्रिया को सरल एवं समयबद्ध बनाया जा रहा है, ताकि निवेश प्रस्ताव तेजी से धरातल पर उतरें और उत्पादन तथा रोजगार सृजन शीघ्र प्रारंभ हो सके।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति को देश-विदेश के निवेशकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। प्रदेश को साढ़े आठ लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। अब सरकार का विशेष जोर इन निवेश प्रस्तावों को तेजी से धरातल पर उतारने पर है। निवेशकों को सुरक्षा और अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों को विशेष प्राथमिकता दी गई है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में औद्योगिक

विकास की नई संभावनाएं आकार ले रही हैं। सरकार की प्राथमिकता है कि औद्योगिकीकरण का विस्तार केवल कुछ क्षेत्रों तक सीमित न रहे, बल्कि प्रदेश के अलग-अलग अंचलों तक पहुंचे। स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों के विकास से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और युवाओं को अपने क्षेत्र में ही रोजगार एवं स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने विश्वास व्यक्त किया कि यश ग्रुप की यह नई इकाई नवा रायपुर और आसपास के क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को गति देने के साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगी। उन्होंने कंपनी प्रबंधन को राज्य सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का भरपूर दिलाले हुए कहा कि परियोजना समयबद्ध रूप से पूर्ण हो और शीघ्र उत्पादन प्रारंभ करे, इसके लिए संबंधित विभाग आवश्यक समन्वय और सहयोग सुनिश्चित करेंगे।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति की सोच में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। अब निवेश का मूल्यांकन केवल निवेश की राशि से नहीं, बल्कि उससे उत्पन्न होने वाले रोजगार के अवसरों के आधार पर भी किया जा रहा है। प्रदेश में लंबे समय तक अधिक पूंजी निवेश और अपेक्षाकृत कम रोजगार देने वाले उद्योगों की प्रधानता रही है। इस स्थिति को बदलते हुए नई औद्योगिक नीति में श्रम आधारित और अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों को विशेष प्राथमिकता दी गई है।

उन्होंने कहा कि यश फैन्स एंड एप्लायंसेस की प्रस्तावित इकाई इसी सोच का उदाहरण है। लगभग 150 करोड़ रुपये के निवेश से साढ़े तीन हजार से अधिक लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन

होना प्रदेश के औद्योगिक विकास की नई दिशा को दर्शाता है। हमारा प्रयास है कि औद्योगिक निवेश का सीधा लाभ छत्तीसगढ़ के युवाओं तक पहुंचे।

श्री चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देश पर वित्त एवं उद्योग विभाग ने समन्वित रूप से औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 तैयार की है। इसमें रोजगार देने वाले उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन देने के साथ केंद्र सरकार की रोजगार प्रोत्साहन योजनाओं से भी समन्वय किया गया है। उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सस्मिडी के बजटीय प्रावधान को लगभग 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर एक हजार करोड़ रुपये से अधिक किया गया है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में राज्य सरकार का पहला बजट 'ज्ञान' अर्थात् गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के कल्याण को समर्पित था, जबकि दूसरे बजट में 'गति' के माध्यम से सुशासन, अधोसंरचना, तकनीक और औद्योगिक विकास को नई गति देने का लक्ष्य रखा गया। आर्थिक विकास से प्राप्त संसाधनों का उपयोग जनकल्याणकारी योजनाओं को और सशक्त बनाने में किया जाएगा। औद्योगिक और आर्थिक प्रगति के माध्यम से जनकल्याण को स्थायी आधार देना सरकार का लक्ष्य है।

उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले ढाई वर्षों में प्रदेश में छोटे-बड़े मिलाकर तीन हजार से अधिक उद्योग स्थापित हुए हैं, जिनके माध्यम से 50 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। आगामी औद्योगिक परियोजनाओं से डेढ़ लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होने की संभावना है।

श्री देवांगन ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण और सरकार की निवेश हितैषी नीतियों के कारण निवेशकों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विस्तारित भारत-2047 के संकल्प के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए उद्योग, निवेश और रोजगार के क्षेत्र में निरंतर काम किया जा रहा है। उन्होंने यश ग्रुप की नई औद्योगिक इकाई को प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कंपनी प्रबंधन को बधाई दी। उन्होंने कहा कि परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा।

पीएम आवास में गड़बड़ी और गरीबों के हक में हेराफेरी बर्दाश्त नहीं होगी : शर्मा

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों और जरूरतमंद परिवारों के आवास निर्माण में किसी भी प्रकार की अनियमितता, लापरवाही और हितग्राहियों के साथ धोखाधड़ी को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इसमें किसी भी स्तर पर गड़बड़ी या हितग्राहियों के हक की राशि का दुरुपयोग कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है कि प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को पक्का आवास मिले। विशेष रूप से दूरस्थ वनांचलों में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

कबीरधाम जिले के विकासखंड बोड़ला अंतर्गत प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के हितग्राहियों से आवास निर्माण



के नाम पर राशि लेकर निर्माण कार्य नहीं करने की शिकायतों पर दो अलग-अलग मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों मामलों में कुल 9 हितग्राहियों से 5 लाख 9 हजार रुपये लेने की शिकायत सामने आई है। संबंधित ठेकेदारों के विरुद्ध थाना चिल्पी एवं थाना तरेगांव जंगल में अपराध दर्ज किया गया है।

ग्राम पंचायत राजाढ़ार के पांच हितग्राहियों से आवास निर्माण के नाम पर कुल 3 लाख 20 हजार रुपये लेने और निर्माण कार्य नहीं करने के मामले में ठेकेदार कुमार मेरवाही के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है।

ग्राम राजाढ़ार निवासी श्री

देवसिंह से 60 हजार रुपये, श्रीमती मंथोर बाई से 60 हजार रुपये, श्रीमती पुसीया बाई से 60 हजार रुपये, श्रीमती कौशल्य बाई से 80 हजार रुपये तथा श्रीमती नमकी बाई से 60 हजार रुपये आवास निर्माण के नाम पर लिए गए थे।

इसी प्रकार विकासखंड बोड़ला की ग्राम पंचायत आमनारा में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के चार हितग्राहियों से आवास निर्माण के नाम पर राशि लेने की शिकायत पर ठेकेदार तुमेश गोड़ के विरुद्ध 13 अक्टूबर को थाना तरेगांव जंगल में एफआईआर दर्ज की गई है।

बैसाख बैगा से 64 हजार रुपये, सुकोर बाई से 60 हजार रुपये, सोनिया बाई से 45 हजार रुपये तथा रनो बाई से 20 हजार रुपये सहित कुल 1 लाख 89 हजार रुपये लेने की शिकायत दर्ज कराई गई है। थाना तरेगांव जंगल में एफआईआर दर्ज की गई है।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब परिवारों के जीवन में सुरक्षा, सम्मान और स्थायित्व लाने का माध्यम है।

सुनीता को रजिस्ट्री में मिली 3,940 की राहत

रायपुर। छत्तीसगढ़ में संपत्ति पंजीयन की प्रक्रिया को सरल, सुगम और किफायती बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए सुधार आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। सूरजपुर जिले की ग्रामीण क्षेत्र की गृहिणी सुनीता के लिए जमीन की रजिस्ट्री कराना अब पहले से अधिक सुविधाजनक और कम खर्चीला हो गया है। महिला क्रेता के रूप में पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट मिलने से उन्हें 3,940 रुपये की प्रत्यक्ष बचत हुई। वहीं रजिस्ट्री के साथ स्वतः नामांतरण की सुविधा से उन्हें अलग से आवेदन करने और राजस्व कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। आर्थिक राहत के साथ समय की बचत ने उनके लिए संपत्ति पंजीयन की प्रक्रिया को अधिक सहज बना दिया।

गंजेपन से मुक्ति
मात्र 1 घंटे में

COMPLETE FAMILY SALON

हेयर स्प्लेसमेंट, 100% संतुष्टि की गारंटी

पहले बाद में

JATU'Z
CUT N SHINE
93009-11331

रंगोली कैलस के सामने, जयसवाल इलेक्ट्रॉनिक के बाजू में इंदिरा मार्केट, स्टेशन रोड, दुर्गा (छ.ग.)

GST NO. 22AHMPB9621P1Z2
PH.: 0748-4060131

अनुप ट्रेडर्स
आर्टिफिशियल ज्वेलरी के विक्रेता
लिंक रोड, केम्प-2, पावर हाउस, भिलाई
मो. 09826389666, 8839749539

खास खबर

पिकअप ने बाइक सवार को मारी टक्कर, चालक फरार

सारागांव। थाना क्षेत्र में 15 अक्टूबर की शाम अज्ञात पिकअप की टक्कर से बाइक सवार युवक घायल हो गया। हादसे के बाद पिकअप चालक वाहन लेकर फरार हो गया। पुलिस अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश कर रही है। ग्राम पंचायत देवरी निवासी विकास कुमार कर्नल (22), पिता रामलाल कर्नल, पीआईएल प्लांट कोटाडबरी चांपा में काम करने के बाद मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था। 6 बजे के बीच सारागांव से चांपा की ओर जा रही तेज स्फारत पिकअप ने मुस्कट्ठी दाईं मंदिर ओवरब्रिज के पास कमरीद मोड़ पर उसकी बाइक को टक्कर मार दी। विकास सड़क पर गिरकर घायल हो गया। उसके दाहिने पैर, हाथ और कंधे में अंदरूनी चोट आई है। मामले की शिकायत सारागांव थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस जांच में जुटी है।

क्राइम ब्रांच का अफसर बनकर युवक से मांगे 15 लाख, एफआईआर दर्ज

रायपुर। क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर एक युवक से 15 लाख रुपए की मांग करने और मारपीट कर उसका मोबाइल छीनने का मामला सामने आया है। आरोपी ने पहले खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर युवक पर दबाव बनाया और फिर लुटपाट कर फरार हो गया। मामले में पुरानी बस्ती थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक, फिलहाल मामले की जांच जारी है। घटना को लेकर अन्य जानकारी सामने आना बाकी है। घटना पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र की बताई जा रही है।

माठागांव बस स्टैंड में खड़ी बस में लगी आग

रायपुर। माठागांव बस स्टैंड में खड़ी रॉयल ट्रैवल्स की बस में शुक्रवार देर रात आग लगने से हड़कंप मच गया। बस के एसी से अचानक धुआं उठने लगा। धुआं देखकर आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। बस में आग लगने की सूचना के बाद वहां मौजूद लोगों के द्वारा आग बुझाने की कोशिश की गई। शुरुआती तौर पर एसी में खराबी के चलते धुआं उठने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है। घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। मामले की जांच की जा रही है।

12 जुआरी दबोचे तो खुला राज पूर्व उपसरपंच खिला रहा सट्टा

खरोरा। सारागांव में ग्वाला पोल्ट्री फार्म के पास जुआ खिलाने के मामले में महीनों से फरार चल रहे पूर्व उपसरपंच उमेश साहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से जुए की रकम 18 हजार रुपये नकद जब्त की गई है। मामले में 12 जुआरी पहले ही जेल भेज चुके हैं। जुआ नेटवर्क से जुड़े उमेश साहू के अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी उमेश साहू को वैधानिक कार्रवाई के बाद न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया।

8 साल के बच्चे का अपहरण, कॉल पर मांगी 15 लाख की फिरोती



श्रीकंचनपथ न्यूज

आरंग। रायपुर जिले में मेडिकल दुकान के पास से 8 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया गया। किडनैपर्स ने परिवार को कॉल पर बच्चे को छोड़ने के लिए 15 लाख रुपये की डिमांड रखी। मामले में त्वरित कार्रवाई से पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। किडनैपिंग में शामिल 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। पूरा मामला आरंग थाना क्षेत्र का है।

मेडिकल दुकान के बाहर से हुई किडनैपिंग

घटना 16 अक्टूबर की सुबह करीब 9 बजे के आसपास की है। आरंग में इंदिरा चौक स्थित मेडप्लस मेडिकल स्टोर के पास से किडनैपिंग हुई थी। काफी देर तक जब बच्चे का पता नहीं तो शाम चार बजे परिजनों ने थाना पहुंचकर शिकायत दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने त्वरित एक्शन लिया। प्रार्थी ने पुलिस को बताया कि वह मेडप्लस मेडिकल स्टोर में काम करता है और उसकी पत्नी नर्स के रूप में कार्यरत है। 16 अक्टूबर को वह अपने 8 साल के बेटे को मेडिकल दुकान पर छोड़ दिया था। बच्चा साइकिल चलाने और खेलने की बाच बोलकर दुकान से बाहर निकल गया था। काफी देर तक वापस नहीं आया। तब परिजनों ने उसे तलाशना शुरू किया। कुछ सुराग नहीं मिलने पर थाने में शाम करीब 4 बजे सूचना दी गई।

वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में मामला लाने के बाद पूरे इलाके में नाकेबंदी करा दी, ताकि आरोपी भाग न पाएं। जब पुलिस आरोपियों की पतासाजी में जुटी हुई थी। इसी बीच प्रार्थी के मोबाइल पर अज्ञात आरोपियों का फोन आया। उन्होंने बच्चे को छोड़ने के लिए 15 लाख रुपये की फिरोती मांगी। कॉल को ट्रेस करने के लिए पुलिस ने तत्काल रेंज साइबर सेल से टेक्निकल सर्विलांस प्राप्त किया। पुलिस ने संभावित सभी रास्तों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस की चौतरफा और सख्त घेराबंदी से घबराए आरोपी खुद को घिरता देख अपहृत बालक को ग्राम समोदा स्थित पेट्रोल पंप के पास छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया।

ट्रकों से बैटरी चोरी करने वाले 06 आरोपी गिरफ्तार 19 बैटरियां के साथ स्कूटी व बाइक को किया जब्त

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। थाना भिलाई भट्टी क्षेत्र में ट्रकों से बैटरी चोरी की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा करते हुए कुल 06 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे एवं निशानदेही पर चोरी की कुल 19 बैटरियां बरामद की गईं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 2,00,000 है। शुरुआती जांच में बीएसपी क्षेत्र, बोरिया गेट एवं चाइना मार्केट के आसपास खड़े ट्रकों तथा ट्रैलर वाहनों से बैटरियां चोरी करने की जानकारी सामने आई। चोरी की बैटरियां खरीदने एवं बेचने में संलिप्तता के संबंध में भी आरोपियों से पूछताछ कर वैधानिक कार्रवाई की को मुर्गा चौक, सेक्टर-01, भिलाई स्थित ओवरब्रिज के नीचे खड़ा कर वह घर चला गया

मिली जानकारी के अनुसार 15 अक्टूबर 2026 को प्रार्थी द्वारा थाना भिलाई भट्टी में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। शिकायत में बताया गया कि 14 अक्टूबर 2026 को एचटीसी प्राइवेट कंपनी के ट्रक को मुर्गा चौक, सेक्टर-01, भिलाई स्थित ओवरब्रिज के नीचे खड़ा कर वह घर चला गया



था। अगले दिन सुबह ट्रक की जांच करने पर उसमें लगी बैटरी गायब मिली। प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध चोरी की बैटरियां बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर संदिग्धों को हिरासत में लिया और पूछताछ की। पूछताछ एवं विवेचना में ट्रकों तथा ट्रैलर वाहनों

से बैटरियां चोरी करने और उन्हें बेचने के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई।

पुलिस ने प्रकरण से संबंधित अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपियों से प्राप्त जानकारी एवं उनकी निशानदेही पर चोरी की कुल 19 बैटरियां बरामद की गईं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 2,00,000 है। इसके अतिरिक्त घटना में प्रयुक्त स्कूटी एवं मोटरसाइकिल जप्त की गईं।

नाबालिग की मौत का आरोपी फरार, पुलिस ने 10 हजार का रखा इनाम

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। दुर्ग के लुचकी तालाब इलाके में नाबालिग लड़की की मौत के मामले में फरार आरोपी रविदास मानिकपुरी (22) पर पुलिस ने 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। दुर्ग पुलिस ने 16 अक्टूबर को बताया कि, आरोपी के बारे में जानकारी देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

नाबालिग का शव 26 सितंबर 2026 को कोतवाली थाना क्षेत्र के वार्ड 7 के एक घर में मिला था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है। मृतका की मां ने रविदास पर मारपीट और काम करारक पैसों न देने का आरोप लगाया था। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी करीब एक साल से रविदास के साथ रह रही थी। घटना से दो दिन पहले बेटी मारपीट से परेशान होकर उनके पास आई थी। 26 सितंबर की शाम रविदास



उसे जबरन अपने साथ ले गया था। मां ने बेटी की मौत के लिए रविदास को जिम्मेदार ठहराते हुए उसके खिलाफकड़ी कार्रवाई की मांग की थी। मामले में इनकी पुष्टि जांच और साक्ष्यों के आधार पर होनी है।

गौ तस्करी के मामले में दो आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल

श्रीकंचनपथ न्यूज

जांजगीर। पुलिस चौकी फगुरम क्षेत्र में गौ तस्करी के दो मामलों में पुलिस ने झारखंड के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपियों की पहचान साहिल खान (37) और शेख सैफ अली (29), निवासी गुमला, झारखंड के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, 2 मई और 9 जुलाई 2026 को गौ सेवकों की सूचना पर वाहनों में कस्तूरतपूर्वक हाथ-पैर बांधकर वध के लिए ले जाए जा रहे गोवंश पकड़े गए थे। अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए

थे। मामले में थाना डभरा की चौकी फगुरम में छत्तीसगढ़ कुपक पशु परीक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किए गए थे। प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के मार्गदर्शन में तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों को पकड़ा गया। उन्होंने स्थानीय व्यक्तिों की मदद से गोवंश खरीदकर वध के लिए ले जाने की बात स्वीकार की। दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस मामले में शामिल अन्य स्थानीय आरोपियों की तलाश कर रही है। कार्रवाई में चौकी प्रभारी अनवर अली सहित पुलिस टीम का योगदान रहा।

श्रीकंचनपथ न्यूज

बेमेतरा। छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए की जा रही कार्रवाई के तहत बेमेतरा जिले में खनिज विभाग ने रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर 6 हाइवा वाहनों को जब्त किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा खनिज संसाधनों के नियमानुसार उपयोग, राजस्व हितों के संरक्षण तथा अवैध खनन गतिविधियों पर नियंत्रण को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी क्रम में जिला प्रशासन द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन की रोकथाम

के लिए निगरानी और प्रवर्तन संबंधी कार्रवाई की जा रही है।

बेमेतरा कलेक्टर प्रतिष्ठ ममगाई के निर्देशानुसार खनिज विभाग की टीम ने 14 एवं 15 अक्टूबर 2026 को ग्राम कठिया-राका और आसपास के क्षेत्रों में जांच अभियान चलाया। इस दौरान रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर 6 हाइवा वाहनों को सुरक्षा संबंधित थाने की अभिरक्षा में रखा गया है। खनिज विभाग द्वारा संबंधित वाहनों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन प्रकरणों



में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 से 23-ख के प्रावधानों के अंतर्गत प्रशमन संबंधी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। संबंधित मामलों में निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

राज्य सरकार द्वारा खनिज संपदा के संरक्षण और उसके वैध उपयोग को सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है। अवैध उत्खनन एवं परिवहन जैसी गतिविधियों से न केवल शासन को राजस्व की हानि हो सकती है, बल्कि

प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित दोहन से पर्यावरणीय संतुलन भी प्रभावित हो सकता है। ऐसे में खनिज नियमों का प्रभावी पालन और अवैध गतिविधियों पर समयबद्ध कार्रवाई आवश्यक है। जिला प्रशासन द्वारा खनिजों के परिवहन की जांच और संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी जारी रखी गई है। खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बेमेतरा जिले में 6 हाइवा वाहनों की जब्तो खनिज कानूनों के प्रवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की दिशा में की गई महत्वपूर्ण कार्रवाई है।

पंडाल के लिए सड़क पर बांधी रस्सी में फंसकर बाइक सवार युवक की मौत



श्रीकंचनपथ न्यूज

अंबिकापुर। शहर के जयसंतंभ चौक में दुर्गा पूजा एवं जागरण कार्यक्रम के दौरान सड़क पर बांधी गई रस्सी में बाइक सवार युवक फंस गए। घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक घायल हो गया। मामले में आयोजन समिति के सदस्यों के खिलाफएफआईआर दर्ज किया गया है। हादसे में जान गंवाने वाले युवक की पहचान मायापुर निवासी फैजान खान के तौर पर हुई है। घटना के बाद कोतवाली थाने में गहमागहमी का माहौल बन गया. पुलिस में

आखिरकार दुर्गा पूजा आयोजन समिति के सदस्य सुरेश कर्नोजिया और संदीप अग्रवाल के खिलाफ धारा 106, 125 एवं 3 के तहत मामला दर्ज किया। दुर्गा पूजा और गणेशोत्सव जैसे आयोजनों के लिए समितियों को जिला प्रशासन अनुमति तो दे देता है, लेकिन इसके बाद निगरानी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसका शिकार फिरोज खान हुआ है। चौक-चौराहों पर बेतरीब तरीके से लगाए जाने वाले पंडालों से न केवल आवाजाही प्रभावित होती है, बल्कि हर समय बजने वाले गानों से लोगों को तकलीफ भी होती है।

भिलाई मसाला उद्योग

शुद्ध कुटे हुए मसाले, पापड़, अचार, बड़ी, जड़ी-बूटी, जचकी का सामान इत्यादि

128, ए- मार्केट, सेक्टर-6, भिलाई, फोन. 2284508, मो. 9826137766

छत्तीसगढ़

में जनजातीय उत्थान



श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



तेंदूपत्ता संग्रहण दर ₹4000
से बढ़ाकर ₹5500 हजार
प्रति मानक बोरा



तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए चरण
पादुका वितरण योजना पुनः लागू



नियद नेल्ला नार योजना से
दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में
बुनियादी सुविधाओं का विस्तार



पीएम जनमन योजना से
कमजोर जनजाति समूहों के
जीवन स्तर में तेजी
से सुधार के प्रयास



जनजातीय उत्सव-पर्वों
के आयोजन के लिए
प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी



आदिवासी बहुल क्षेत्रों में
स्थानीय भाषा-बोलियों
में स्कूली शिक्षा



RO- 49456/3

हमसे जुड़ने के लिए
यह Q.R. Code
स्केन करें



जनजातीय समुदाय के
संरक्षण- संवर्धन और उत्थान
के लिए प्रतिबद्ध
विष्णु देव सरकार

सुशासन से समृद्धि की ओर

Visit us : [ChhattisgarhCMO](#) [ChhattisgarhCMO](#) [ChhattisgarhCMO](#) [ChhattisgarhCMO](#) [DPRChhattisgarh](#) [DPRChhattisgarh](#) [www.dprcg.gov.in](#)

